वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमानों पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2016–2017 का बजट इस संकल्प के साथ सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ''जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं है ।''

मान्यवर,

इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से मुझे इस ऐतिहासिक और गरिमामय सदन में लगातार पाँचवी बार बजट पेश करने का मौका मिला है । चुनाव के बाद शुरूआत के सालों में कोशिश थी कि विधानसभा के चुनाव के समय हमने जनता को जो वायदे किए थे उनको पूरा किया जाये और आप सबके सहयोग से हमने अधिकांश वायदों को पूरा भी किया है । आज मुझे इस सदन को बताते हुए संतोष है कि तमाम प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों के बावजूद हमने इस बजट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाने हेतु व्यवस्था की है ।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने हमेशा सदन में कहा है कि हम समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहता है । कई बार हमें अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाईयाँ आयीं और परिस्थितियाँ

हमारे अनुमान को झटका दे गयी पर उससे हमारी हिम्मत में और उफान आया ।

"जबसे पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया,
मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा ।"

हमारी सरकार ने अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के साथ–साथ नये इरादों के साथ तरक्की का शुभारम्भ किया है और नयी–नयी दिशाओं में काम शुरू किया है ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके । इसी दिशा में हमारी सरकार ने हर साल विकास का एक एजेण्डा जनता के सामने रखा है और फिर पूरे वर्ष उस पर ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया गया है । आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के साथ–साथ बाहर से आने वाले लोग भी यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों से अधिक और तेज विकास हो रहा है और विकास की योजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही है । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के आंकड़ो में भी उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक पूँजीगत व्यय करने वाला राज्य हो गया है । जानकार लोग यह मानते हैं कि पूँजीगत व्यय में वृद्धि से प्रदेश को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया गया है ।

हमारे विकास के एजेण्डा के पीछे जो मूलभूत सिद्धान्त रहा है, वह है सहभागी और संतुलित विकास । एक ओर हमने प्रदेश की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिए तत्परता से काम किया और इस दिशा में बुनियादी ढाँचे में पूँजी निवेश किया, बेहतर और व्यवहारिक नीतियाँ बनाई और एक स्वस्थ और पारदर्शी

माहौल लोगों को दिया, वहीं दूसरी ओर हमारी कोशिश रही कि इस बढ़े हुए विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कमजोर लोगों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित लोगों को मिले । इसलिए जहाँ एक ओर लखनऊ के साथ–साथ नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो निर्माण का कार्य किया जा रहा है और आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद में मेट्रो के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, वहीं हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम–समाजवादी पेंशन योजना भी लागू की गयी है । हमने न केवल हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य से अधिक तीन करोड़ छः लाख लोगों के बैंक खाते खोले बल्कि पैंतालीस लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को उनके खातों में सीधे पेंशन की धनराशि भेजने की व्यवस्था की है । मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने बजट प्रस्तावों में समाजवादी पेंशन योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर पैंतालीस लाख से पचपन लाख करने का प्रस्ताव रखा है । वृद्धावस्था पेंशन से 39 लाख, विधवा पेंशन योजना से 16 लाख तथा विकलांगता पेंशन से 8 लाख लाभार्थी आच्छादित हैं । इस प्रकार इन योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख से अधिक है । इस प्रकार प्रदेश की पूरी आबादी लगभग 20 करोड़ में से लगभग सवा करोड़ जनसंख्या जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, को हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने का काम किया है ।

इसके अतिरिक्त "कृषक दुर्घटना बीमा योजना" से 2 करोड़ 50 लाख किसान खातेदार आच्छादित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक के आयु के मुखिया सदस्य के आश्रितों को "आम आदमी बीमा योजना" में लाभ दिया जा रहा है । वर्ष 2016–2017 में कृषक दुर्घटना बीमा के स्थान पर "समाजवादी सर्वहित बीमा योजना" प्रस्तावित की जा रही है । पुरानी योजना में केवल मृतक के परिवारजनों को 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाता था जबकि नई प्रस्तावित योजना में मृतक के परिवार को तथा दुर्घटना में गंभीर रूप से विकलांग हुये व्यक्ति को भी 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त इस योजना में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए 2.50 लाख रुपये दिये जाने का प्राविधान है और किसी घायल व्यक्ति को यदि कृत्रिम अंग लगाया जाता है तो उसके लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी । पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिये भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

जहाँ हम देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे आगरा से लखनऊ बना रहे हैं जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को अपनी उपज को बाजार में लाने–ले जाने की सुविधा मिले, वहीं हम हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा 102/108 के अर्न्तगत 3,500 से अधिक एम्बुलेंसों का प्रतिदिन संचालन करवा रहे हैं । लखनऊ एयरपोर्ट से

चारबाग रेलवे स्टेशन तक आते वक्त हर कोई लखनऊ मेट्रो के काम को देख सकता है और मुझे यह आशा है कि जब मैं अगले साल बजट सदन में प्रस्तुत करूँगा तब उस समय आप में से कई सम्मानित सदस्यगण उस मेट्रो पर बैठकर सदन में आ सकेंगे । आज कोई भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे के तेजी से हो रहे निर्माण को देख सकता है और हम पूरी कोशिश कर रहे है कि इस एक्सप्रेस–वे में इसी साल ट्रैफिक दौड़ना शुरू कर दे । मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसी तरह का एक एक्सप्रेस–वे "समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेव–वे" का प्रस्ताव बजट में रखा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को लखनऊ से जोड़ेगा, जिससे नई दिल्ली और नोएडा क्षेत्र का विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँच सके ।

मान्यवर, हम समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि इस देश और प्रदेश की खुशहाली तभी हो सकती है जब किसान और गाँव खुशहाल रहे और इसीलिए कृषि और उससे संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने वर्तमान वर्ष को ''किसान वर्ष'' घोषित किया है ।

यद्यपि मौसम के ऊपर किसी का जोर नहीं है फिर भी राज्य सरकार ने आप सबके सहयोग से किसानों के संकट के समय में सबसे तेज और सबसे अधिक राहत सहायता उदारता के साथ पहुँचायी है । हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से किसानों के लिए जितनी मदद माँगी थी, वह हमें नहीं मिल सकी परन्तु हमने उसकी परवाह किए बिना इस सदन के सहयोग से आकस्मिकता निधि की

सीमा को बढ़ाकर अपने खजाने से किसानों को राहत पहुँचायी है । इसके अलावा भी राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। आप सब जानते ही होंगे कि इस साल प्रमाणित बीजों के वितरण में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश में 10 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे अनुदान राशि भेजी गयी है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पहला राज्य बन गया है । हमने न केवल किसानों के हित में सिंचाई को मुफ्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया बल्कि खादों के अग्रिम भण्डारण की ऐसी व्यवस्था अपनायी जिससे किसानों को समय से खाद मिल सके । हमने कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया और खेती के साथ–साथ खेती से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में भी तत्परता से काम किया ताकि किसानों को आय के स्रोत मिल सके । कामधेनु योजना और कुक्कुट नीति के अन्तर्गत सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले । जहाँ एक ओर अमूल की डेयरियों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है वहीं हमने पी.सी.डी.एफ. को मजबूत करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया ताकि दुग्ध उत्पादकों के बीच कम्प्टीशन बढ़े ताकि जहाँ किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके वहीं लोगों को अच्छी गुणवत्ता का दूध मिल सके ।

मान्यवर, आप सब जानते हैं कि जब केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे हिन्दुस्तान के बाजार में चीनी के भाव लुढ़कने लगे थे तब उत्तर प्रदेश की ही सरकार थी जिसने अपने बजट से सीधे किसानों

के खातों में धनराशि मुहैया करायी ताकि किसानों को नुकसान न हो और मिलें भी बंद न हों ।

मान्यवर, यह प्रदेश एक युवा प्रदेश है । बड़ी संख्या में युवक और युवतियों का जोश, उत्साह और उनकी नई सोच इस प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का शुभारम्भ करेगी । यह हमारी सरकार का दायित्व है कि हम उनकी शिक्षा हेतु बेहतर अवसर पैदा करें और उनके रोजगार के साधन तैयार करें ताकि उनका भविष्य खुशहाल हो सके ।

मान्यवर, मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2016–2017 को ''किसान वर्ष और युवा वर्ष'' घोषित करने का निर्णय लिया है और हम पूरे वर्ष किसानों और युवाओं की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं पर तत्परता से काम करेंगे जिनकी रूपरेखा मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करूँगा ।

मान्यवर, हमारी सरकार पहले से भी विभिन्न सेक्टर्स में रोजगारपरक योजनायें और कार्यक्रम संचालित कर रही है । लघु उद्योग क्षेत्र में "समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना" लाई जा रही है जिसके माध्यम से युवाओं को अपने रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी । प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु "एग्री जंक्शन योजना" संचालित है । पशु पालन के क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान की योजना लाई जा रही है ।

युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु रोजगार मेलों के आयोजन तथा युवाओं के कैरियर काउन्सलिंग की योजना लाई जा रही है जिससे उन्हें सही दिशा में अपना कैरियर चुनने में मदद मिलेगी । छात्र–छात्राओं को मेरिट आधारित निःशुल्क लैपटॉप वितरण तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने हेतु संशोधित कन्या विद्याधन योजना भी युवाओं के लिये संचालित है । प्रत्येक वर्ष लाखों युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है । इन विशिष्ट लाभार्थी आधारित योजनाओं के अलावा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये सामान्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

मैं बताना चाहूँगा कि बाँदा, बिजनौर, अम्बेडकर नगर मैनपुरी, कन्नौज और सोनभद्र में इन्जीनियरिंग कॉलेजों में पठन–पाठन का कार्य 2015–2016 में प्रारम्भ किया जा चुका है तथा आजमगढ़ में निर्माणाधीन इन्जीनियरिंग कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2016–2017 से कक्षायें प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । देवीपाटन एवं बस्ती मण्डल में एक–एक इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा लखनऊ में इण्डियन इस्ट्टीयूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करायी जा रही है । राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज, आजमगढ़, जालौन एवं सहारनपुर को प्रारम्भ किया जा चुका है । बाँदा, जौनपुर, चन्दौली एवं बदायूँ में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है । जनपद बिजनौर के नजीबाबाद

में नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस प्रकार से प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों की संख्या 16 हो जायेगी । प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों की संख्या 1,140 थी जिसमें 500 सीटों की वृद्धि की गई है । अब तक के हमारे कार्यकाल में 80 नये आई.टी.आई स्वीकृत किये गये तथा 1200 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ–साथ 21 पॉलीटेक्निकों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया तथा जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज एवं जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में नये पॉलीटेक्निक की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है ।

मान्यवर, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को तेज करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं में सुधार किया, नीतियाँ बनायी और बेहतर स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराया । मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि आज प्रदेश में रिलायन्स, आई.टी.सी., एस्सेल, गेल, एमिटी, फोर्टिस जैसे तमाम प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों ने परियोजनायें लगाने के लिये राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये हैं । इन परियोजनाओं में लगभग 42,500 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है । हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत 5,427 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश तथा 33 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में 7,587 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हो चुका है । आने वाले वर्षों में हमारी सरकार प्रदेश के वर्तमान शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के साथ–साथ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में

एक–एक ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने के लिए काम करेगी जहाँ लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर, स्वस्थ वातावरण, रोजगार के मौके और सभी नागरिक सुविधाएं मिल सके । इससे न केवल निजी निवेश आकर्षित होगा बल्कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव मिल सकेगा ।

हमारा यह विश्वास है कि विकास की कुँजी बेहतर अवस्थापना में है । मेट्रो एवं एक्सप्रेस–वे के अलावा भी हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ने तथा सैकडों पुलों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । अभी हाल ही में मेरे द्वारा स्वंय बहराईच से श्रावस्ती और कालपी से हमीरपुर फोर लेन सड़कों का लोकार्पण किया गया और आने वाले महीनों में इलाहाबाद–जौनपुर–आजमगढ़ मार्ग, फैजाबाद–अकबरपुर–बसखारी मार्ग, भदोही–मिर्जापुर मार्ग और छिबरामऊ–सौरिख–विधूना मार्ग को फोर लेन किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जनपद बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी पर 2,544 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जो प्रदेश का सबसे लम्बा पुल होगा । जनपद बलिया में ही चाँदपुर गाँव के पास घाघरा नदी पर 1,314 मीटर लम्बे पुल का भी निर्माण कराया जायेगा ।

मान्यवर, हमारी सरकार अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसलिए हम न केवल बिजली की उपलब्धता को

11,000 मेगावॉट से बढ़ाकर 21,000 मेगावॉट करने वाले हैं बल्कि हमने रिकॉर्ड संख्या में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब–स्टेशनों और लाइनों का निर्माण भी कराया है ताकि बिजली वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुँच सके । हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक गाँव में बिजली उपलब्ध करायी जाये और इस दिशा में कार्ययोजना बनाकर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है । पिछले एक वर्ष में 30 लाख से अधिक परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं जो आज तक इस सुविधा से महरूम थे । पारम्परिक ऊर्जा के साथ–साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गये हैं और पिछले तीन सालों में पूरे प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन पहले के मुकाबले 10 गुना हो गया है । साथ ही राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 70,000 सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना तथा 40,000 लोहिया आवासों में सोलर पैक का प्रावधान किया गया है। कन्नौज के 2 गाँव सोलर ऊर्जा से पूर्णतः ऊर्जीकृत किये गये हैं ।

मान्यवर, प्रदेश में सिंचाई की कुछ वृहद परियोजनायें कई वर्षों से मन्थर गति से चलने के कारण अधूरी पड़ी हुई थीं, हमारी सरकार ने संसाधनों को एकजुट करके इनको पूरा करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं । वृहद सिंचाई परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सरयू नहर परियोजना है जिसके पूर्ण हो जाने पर अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख हेक्टेअर की सिंचाई शुरू हो सकेगी जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक रूप से कायाकल्प होने के साथ ही प्रदेश के विकास को गति

मिलेगी । इसके साथ ही बाण सागर नहर परियोजना और कनहर सिंचाई परियोजना के लिए भी समुचित धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिससे अब ये परियोजनायें तेजी से पूरी हो रही हैं । हमारी सरकार प्रदेश के राजकीय नलकूपों और लघु डाल नहरों की बिजली आपूर्ति के समाधान के लिए ग्रिड ऊर्जा के साथ–साथ उन्हें सौर ऊर्जा से चलाये जाने की दिशा में भी काम करेगी ।

मान्यवर, अधिक से अधिक परिवारों को बैंको से और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का हमने प्रयास किया जिसके फलस्वरूप मार्च, 2012 से सितम्बर, 2015 तक की अवधि में 3,889 नई बैंक शाखायें प्रदेश भर में खोली गयी हैं । यह इस बात का भी द्योतक है कि इस अवधि में फाईनेन्शियल इन्क्लूजन भी प्रभावकारी रूप से प्रदेश में बढ़ा है । बैंकिंग तथा इन्श्योरेन्स हेल्प लाईन 1520 प्रारम्भ की गई है जिसका प्रयोग कर बैंकिंग और इन्श्योरेन्स से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है और व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण भी कराया जा सकता है ।

मान्यवर, शहरों के साथ–साथ हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास की कई योजनायें संचालित की जा रही है । डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत लगभग 10 हजार ग्रामों में 18 विभागों के 34 कार्यक्रम संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में मुख्य रूप से सी.सी. रोड व नाली निर्माण का कार्य कराने की व्यवस्था है । इस योजना के

अन्तर्गत अब तक 3,908 ग्राम स्वीकृत हुये हैं । इस योजना में प्रत्येक गाँव में लगभग 40 लाख रुपये से कार्य कराये जाने की व्यवस्था है ।

अब तक 5,802 समग्र ग्रामों का चयन कर अवस्थापनापरक आधारभूत सुविधाओं व व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं से गाँवों का पूर्ण विकास करते हुये लगभग 1,659 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया है । वर्ष 2015–2016 में 2,098 ग्राम चयनित किये गये है जिन पर कार्य चल रहा है । वर्ष 2016–2017 में 2,100 ग्राम चयनित किये जाने का लक्ष्य है ।

मान्यवर, इस सदन में प्रस्तुत बजट में गाँवों के लिए एक नयी योजना ''आई स्पर्श'' के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गयी है जिसमें चुने गये गाँवों को नयी सुविधाओं से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

मान्यवर, प्रदेश के बहुमुखी विकास तथा जनसाधारण में सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था आवश्यक है जिसके लिये हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा उसकी पहुँच जन सामान्य तक सहज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । इनमें महिलाओं को परेशान करने या सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिये 1,090 पर फोन करके पुलिस की मदद प्राप्त करने हेतु वीमेन पॉवर लाईन विशेष उल्लेखनीय हैं जिसकी सराहना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है । अब तक लगभग 3 लाख 43 हजार शिकायतों का निस्तारण कर महिलाओं को सहायता प्रदान

की जा चुकी है । डायल 100 सेवा का संचालन किया गया है जिसके द्वारा जन साधारण को पुलिस की सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है । इस योजना को व्यापक रूप देकर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है । जनसाधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने एवं उनके साथ विनम्रता एवं भद्रता के साथ पेश आने के लिये पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से कॉन्स्टेबल्स व उपनिरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ।

अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम लखनऊ में लागू किया गया है और अब इसे 11 और नगरों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है । इससे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होगी और जुलूस, प्रदर्शन पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा । पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिये अत्याधुनिक फोरेन्सिक लैब्स की स्थापना की जा रही है, थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा, प्रति थाना दो नये वाहन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया जा रहा है । सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने के लिये अराजक तत्वों द्वारा किये गये कतिपय प्रयासों को पुलिस बल के द्वारा सख्ती के साथ हर मौके पर प्रभावी कार्यवाही कर काबू किया गया और सामाजिक सद्भाव को बनाये रखा गया है । इन प्रयासों से जनसाधाण में सुरक्षा की भावना बलवती हुई है ।

मान्यवर, हमने पिछले चार सालों में प्रदेश में एक स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शी माहौल दिया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि जनता की खुशहाली तभी संभव है जब सरकार और समाज एक साथ मिलकर काम करें इसीलिए

हमने प्रतिभावान साहित्यकारों, विचारकों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कवियों और अन्य लोगों को सरकार के साथ जोड़ा है, उनको सम्मानित किया है । वर्षों से रूके हुए पुरस्कारों को फिर से शुरू किया गया है और नये पुरस्कार भी हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये हैं । कुछ ही दिनों पूर्व मैंने प्रतिभावान अप्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों को यू.पी. रत्न से सम्मानित किया ।

मान्यवर, मुझे इस गरिमामयी सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में दी जा रही मासिक पेंशन की धनराशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,176 रुपये तथा लोकतंत्र सेनानियों को वर्तमान में स्वीकृत 10 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया जा रहा है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान का दिल भी कहा गया है और लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान के हर प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश से निकलता है । आप सबके सहयोग से पिछले चार सालों में हमने प्रदेश में विकास के नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर उत्तर प्रदेश को एक गौरवशाली मुकाम तक पहुँचाया है और इसकी वजह से पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है चाहे वह विकास की दर की बात हो, पूँजीगत व्यय की दर की बात हो, लखनऊ मेट्रो हो, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, डी.बी.टी. योजना हो, सोलर पॉवर पैक की योजना हो, 102/108 एम्बुलेंस हो, किसान दुर्घटना बीमा योजना हो,

लोहिया आवास योजना हो, समग्र ग्राम विकास योजना हो या कोई अन्य योजना ।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

किसानों और गाँवों के लिए

कृषि

- किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिये 1,336 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।
- किसानों की गन्ना उपज को मिलों तक पहुँचाने तथा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के लिये सम्पर्क मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 120 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- किसानों और जनसामान्य के लक्षित समूह के व्यक्तियों हेतु "समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 897 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आम आदमी बीमा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राज्य आपदा मोचक निधि से राहत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 709 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के 73 जनपदों में फरवरी/मार्च/अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई थी । प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु अब तक कुल 4498 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- वर्तमान मानसून में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है । सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति से निपटने के लिये 2057 करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार की गई है ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 787 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अल्पकालिक फसली ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2016–2017 में 150 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 75 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

- जनपद बहराइच में किसान बाजार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
- सूखाग्रस्त जनपदों में अतिरिक्त चारा दाना विकास कार्यक्रम प्रस्तावित है ।
- जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- सरकार के विशेष प्रयास से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । वर्ष 2015–2016 में 89 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में 98 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है ।
- खाद, बीज आदि के क्रय हेतु किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्ष 2016–2017 में 93,212 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित कराये जाने का लक्ष्य है ।
- वर्ष 2015–2016 में 627 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 660 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है ।
- वर्ष 2016–2017 में 56 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 45 लाख कुन्तल का बीज वितरण किया जाना प्रस्तावित है । वर्ष

2016–2017 में 42 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है ।

- फसल बीमा कार्यक्रमों हेतु 450 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- भूमि सेना योजना हेतु 83 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं मंहगें डीजल/विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु वर्ष 2016–2017 में कृषकों के खेतों पर सोलर फोटोवोल्टइक पम्प की स्थापना के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्राविधान किया गया है ।
- प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016–2017 में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना के अन्तर्गत 1,000 एग्री जंक्शन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।
- विभिन्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले तीन कृषकों को 20,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तम कृषक पुरस्कार "किसान दिवस" के अवसर दिया जाता है जिसकी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये किये जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त प्रदेश की तीन प्रगतिशील महिला कृषकों को भी पृथक श्रेणी के अन्तर्गत इसी के अनुसार प्रथम,

द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

- इस वर्ष प्रमाणित एवं संकर बीजों के वितरण में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर का प्रयोग करते हुये दस लाख से अधिक किसानों के खातों में अनुदान का वितरण किया गया है । उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है ।
- आगामी वित्तीय वर्ष में बुन्देलखण्ड में खरीफ के दौरान आच्छादन बढ़ाने के लिये इस वर्ष की भाँति तिल के बीजों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान यथावत् रखा जाएगा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

प्रदेश में वैज्ञानिक रीति से कृषि को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार द्वारा कृषि शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों में विस्तार किया गया है और इसके लिये पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है ।

- जनपद–आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नये कृषि महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा पठन–पाठन विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ करा दिया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में इस हेतु 28 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे चालू योजनाओं को समय से पूर्ण किया जायेगा तथा जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन नये कृषि महाविद्यालय को शीघ्र चालू कराया जायेगा ।

दुग्ध विकास

हमारा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है । हमारी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन और विपणन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे हैं । प्रदेश में प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ का पुनर्गठन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है । इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय की निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों को प्रदेश में अपनी इकाईयाँ स्थापित किये जाने की योजनायें भी क्रियान्वित की जा रही है ।

- दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण योजना, कृषक प्रशिक्षण योजना तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों / समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम के माध्यम से पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन योजनाओं हेतु 41 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लान्टों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पशुपालन

- प्रदेश सरकार ने पहली बार पशुधन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है । वर्ष 2015–2016 में माह दिसम्बर, 2015 तक

191 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ । वर्ष 2016–2017 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 362 लाख मीट्रिक टन रखा गया है ।

- वर्ष 2016–2017 में ''उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013'' के अन्तर्गत ब्रॉयलर पैरेण्ट फार्मिंग की 10 इकाई तथा कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की 90 इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।
- मार्च, 2017 तक कामधेनु, मिनी कामधेनु तथा माइक्रो कामधेनु इकाईयों का लक्ष्य क्रमशः 300, 1500 तथा 2500 इकाई रखा गया है ।
- बहुउद्देश्यीय सचल पशु चिकित्सा सेवा के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना के लिये 51 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान की योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जोखिम प्रबन्ध और पशुधन बीमा योजना के लिये 18 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- बाबूगढ़ और रहमान खेड़ा में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की ग्रेडिंग में सुधार के लिये 28 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

मत्स्य

- 5000 हेक्टेअर सामुदायिक तालाबों को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा और निजी क्षेत्र में 1,000 हेक्टेअर जलक्षेत्र के नये तालाब निर्मित कराने तथा प्रोत्साहन स्वरूप लाभार्थियों को देय अनुदान सुलभ कराये जाने का प्रस्ताव है ।
- 60,000 व्यक्तियों को मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।
- मछुआ समुदाय के 2 लाख 5 हजार समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा ।
- मछुआ समुदाय के आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

परती भूमि विकास

- प्रदेश के 29 ऊसर बाहुल्य जनपदों में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन–तृतीय ऊसर सुधार की परियोजना का संचालन किया जा रहा है ।
- परियोजना के अन्तर्गत 01 लाख 30 हजार हेक्टेअर ऊसर सुधार का लक्ष्य निर्धारित है । बीहड़ सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना में जनपद कानपुर देहात एवं फतेहपुर में पायलेट आधार पर 5,000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित है ।

- परियोजनान्तर्गत अब तक 438 मुख्य जल निकास नालों के पुनरोद्धार के माध्यम से लगभग 03 लाख 72 हजार हेक्टेअर भूमि में जल भराव की समस्या का निराकरण कराया गया है ।

कृषि विपणन

- प्रदेश में मण्डी परिसरों के घनत्व को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में एक मण्डी परिसर की स्थापना कराये जाने हेतु 1,645 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,643 हब्स का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें 911 हब संचालित कर दिये गये हैं।
- कृषकों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 06 जनपद–लखनऊ, झाँसी, सैफई (इटावा), मैनुपरी, कन्नौज और कासगंज में किसान बाजार का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है जिसमें से झाँसी का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा लखनऊ, सैफई (इटावा), मैनपुरी, कन्नौज एवं कासगंज में निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
- फल सब्जी के लघु एवं सीमांत कृषक उत्पादकों के उत्पाद को निकटतम मण्डी में लाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मण्डी परिषद द्वारा प्रथम चरण में 05 मण्डियों यथा–कन्नौज, बहराइच, कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना परीक्षण के तौर पर आरम्भ की

गयी । साथ ही दुग्ध उत्पादन की सुविधा हेतु जनपद गाजीपुर से वाराणसी तक दुग्ध के निःशुल्क परिवहन हेतु 02 बसें चलायी जा रही है ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विशिष्ट मण्डियों के निर्माण कराये जाने की श्रंखला में 07 विशिष्ट मण्डियों हेतु कुल 434 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के लिये 254 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिसमें से 129 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 79 केन्द्र क्रियाशील हो चुके हैं ।
- कन्नौज में 102 करोड़ रुपये की लागत से आलू की विशिष्ट मण्डी तथा मलिहाबाद में 79 करोड़ रुपये की लागत से आम की विशिष्ट मण्डी का निर्माण वर्ष 2016–2017 में प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं तथा उनके संचालन व्यय हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बागवानी विकास हेतु वर्ष 2016–2017 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौंध मिशन, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन योजना आदि कार्यक्रम संचालित किये जायेगें जिनमें किसानों को

मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी ।

- प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि विपणन और निर्यात को प्रोत्साहन तथा गुणवत्तायुक्त आलू बीज का उत्पादन और वितरण कराये जाने के उद्देश्य से आलू विकास नीति, 2014 लागू की गई है ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत फल–सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, माँस, बेकरी आधारित उद्योग आदि सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और गाँवों को तेजी से विकास की राह पर लाने तथा गाँवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का समुचित विकास कराया जाये । हमारी सरकार ने गाँवों में सड़कों, सेतुओं, बिजली, सिंचाई सुविधा, पक्के आवासों, पेयजल, शौचालय, सी.सी. रोड, नाली आदि की व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम सघन रूप से चलाये गए हैं ।

- समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण कार्यों के लिये 630 करोड़ रुपये की

बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अन्य कार्यों के लिये 1,413 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिये 2,300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु 1,779 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- इन्दिरा आवास योजना के लिये 3,162 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- आई स्पर्श योजना के अन्तर्गत गावों को स्मार्ट विलेज बनाये जाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पंचायती राज

- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन इण्टरलॉकिंग और टाईल्स की व्यवस्था हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के लिए 1,536 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 127 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है । इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण

क्षेत्र के अवशेष समस्त अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किया जायेगा ।

बुन्देलखण्ड के लिए विशेष

- बुन्देलखण्ड की विशेष जरूरतों को देखते हुए हमने इस क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय संसाधनों में काफी वृद्धि की है ।
- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।
- बुन्देलखण्ड में पेयजल की विशेष व्यवस्था के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में सरफेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिये 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 338 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बुन्देलखण्ड में टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बुन्देलखण्ड में तिलहन प्लान्ट की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

विश्वस्तरीय अवस्थापना की ओर

बिजली

आज के युग में उद्योग, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता पहली

आवश्यकता बन गयी है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक गाँव में बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग 1,73,000 गाँवों एवं मजरों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 11,900 करोड़ रुपये लागत की योजना तैयार की गई है ।
- वर्ष 2015–2016 में एक लाख गाँवों एवं मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा कृषि कार्यों हेतु कम से कम 8 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने फीडर सेपरेशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है । इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी है ।
- कृषि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
- हमारी सरकार का प्रयास होगा कि अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो सके ।
- मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि न सिर्फ बढ़ी हुई विद्युत आपूर्ति वरन् 2019–2020 से कटौती मुक्त 24x7 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु

सरकार प्रतिबद्ध है एवं इसके लिये कार्य योजना बनाकर कार्यवाही भी की जा रही है ।

- हमारी सरकार एवं वितरण कम्पनियों द्वारा अक्टूबर, 2016 तक विद्युत उपलब्धता वर्तमान में लगभग 11,000 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 21,000 मेगावाट करने हेतु सभी प्रबन्ध कर लिये गये हैं ।
- इसी क्रम में विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय पुनर्गठन की योजना "उदय" के क्रियान्वयन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 39,909 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रदान की जायेगी । राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी ।

सड़क और पुल

मान्यवर,

प्रदेश की प्रगति के लिये गुणवत्तापूर्ण सड़कों के नेटवर्क का होना अति आवश्यक है और यह हमारे विकास कार्यक्रम में प्रमुख स्थान रखता है ।

- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख–रखाव हेतु 14,721 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं तथा प्रमुख मार्गों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 541 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 3,205 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु कुल 1,923 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1,180 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 635 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 1,111 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों का एक कोर रोड नेटवर्क चिन्हित कर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जायेगा जिसके लिये 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के सौंदर्यीकरण / उच्चीकरण हेतु भी 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है ।

- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु 320 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना हेतु 260 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्ग हेतु 257 किलोमीटर लम्बाई के कार्य प्रगति में है । इस परियोजना के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 220 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना में सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, आदि के कार्यो को प्राथमिकता पर कराया जा रहा है । वर्ष 2016–2017 में योजना के लिये 900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नगर विकास

प्रदेश के नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के मद्देनजर नगरों में बसने वाले सभी सामाजिक आर्थिक समूहों के लिये स्वच्छ, प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यकर निवास क्षेत्र और सुरक्षित पेयजल के साथ–साथ नगरों में उत्कृष्ट अवस्थापना की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के प्रति हमारी सरकार सजग है ।

- स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष

2016–2017 में क्रमशः 600 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये तथा 700 करोड रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना में 200 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज योजना में 50 करोड रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 335 करोड़ रुपये, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिए 130 करोड़ रुपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिए 140 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु रुपये 300 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नया सवेरा नगर विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलिवेटेड पहुँच मार्ग एवं फ्लाई ओवर निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नगर निकायों में सौर ऊर्जा पॉवर प्लाण्ट के माध्यम से स्ट्रीट लाईट और पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय शहरी पुँज योजना" के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- शहरी यातायात विकास फण्ड के लिये लगभग 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश की शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अलपसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी.सी. रोड, इंटरलॉकिंग टाईल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के कार्यों हेतु 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवास एवं शहरी नियोजन

- लखनऊ विकास क्षेत्र और प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनेश्वर मिश्र पार्क के संचालन और नवीनीकरण के लिये 150 करोड़ रुपये से कॉर्पस फण्ड का गठन किये जाने का प्रस्ताव है ।
- आगरा इनर रिंग रोड फेज–2 तथा फेज–3 के निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- शान–ए–अवध संकुल के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कानपुर एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के लिये 50–50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु वर्ष 2015–2016 में दिये गये 625 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में 814 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के चयनित शहरों में मॉडल सिटीज के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सिंचाई

कृषि प्रधान प्रदेश में सिंचाई का विशेष महत्व हैं इसलिये हमारी सरकार इसके लिये संवेदनशील है ।

- सिंचाई कार्यक्रमों की नई योजनाओं के लिये 1,574 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के लिये 745 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपद झाँसी में बेतवा नदी पर एरच के पास सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजना के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अर्जुन सहायक परियोजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिये 2,157 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- गोमती नदी के चैनलाइजेशन के लिये 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वरूणा नदी के चैनलाइजेशन और तटीय विकास के लिये 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण की परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लघु सिंचाई

- वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है। वर्ष 2016–2017 हेतु 549 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 36 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- मध्यम गहरे नलकूप योजना हेतु 84 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- गहरी बोरिंग योजना हेतु 19 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु 7 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास

मान्यवर,

औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश के समग्र विकास का सपना साकार नहीं हो सकता । औद्योगिक विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण अवस्थापनाओं और प्रोत्साहन स्वरूप नीतियों का होना आवश्यक है । हमारी सरकार ने इस कमी को महसूस किया और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देते हुये उद्योग जगत के साथ सशक्त संवाद स्थापित किया गया । इसके सार्थक परिणाम प्रदेश में दिखाई पड़ने लगे हैं ।

- लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे के निर्माण हेतु 4,003 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- लखनऊ–आजमगढ़–बलिया समाजवादी एक्सप्रेस–वे के लिये 1,500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- यमुना एक्सप्रेस–वे पर स्थापित किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पॉवरलूम विकास योजना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- एकीकृत औद्योगिक नगरी (संगम सिटी) क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ।

इस परियोजना के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के अन्तर्गत दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र एवं तीन अर्ली बर्ड परियोजनाओं यथा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्राँसपोर्ट हब विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
- कालिन्दी कुँज से बॉटनिकल गार्डेन एवं नोएडा सिटी सेक्टर 32 से सेक्टर 62 तक मेट्रो लाईन का विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
- वर्ष 2015–2016 में माह नवम्बर, 2015 तक 40,240 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हुई जिसमें 3,49,329 रोजगार सृजित हुये एवं 4,394 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है ।
- प्रदेश के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है । वर्ष 2013–2014 में कुल निर्यात 80,523 करोड़ का था जिसके सापेक्ष वर्ष 2014–2015 में बढ़कर 85,034 करोड़ रुपये हो गया ।
- प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "निर्यात नीति उत्तर प्रदेश, 2015–2020" जारी की गई है ।

परिवहन

- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बस स्टेशनों के पुनर्निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- आजमगढ़ तथा गौतमबुद्ध नगर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय के निर्माण हेतु क्रमशः 17 करोड़ रुपये तथा 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

- जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, परिष्कृत एवं व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 13 शहरों–लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झाँसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर में रेडियो टैक्सी के संचालन का निर्णय लिया गया है जिसमें लखनऊ एवं वाराणसी महानगर में रेडियो टैक्सी का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

नयी पीढ़ी और युवाओं के लिए

बेसिक शिक्षा

- सर्व शिक्षा अभियान के लिये 15,397 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को फल वितरण किये जाने की नई योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश के ग्रामों/मजरों में विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य को वर्ष 2016–2017 में पूर्ण कराये जाने के लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मॉडल प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं के लिए 9,168 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- संशोधित कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा 30 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान किये जाने के लिए 300 करोड रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क लैपटॉप दिया जाना प्रस्तावित है । इस योजनान्तर्गत 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के तीन जनपदों–अमेठी, मैनपुरी तथा झाँसी में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के 18 मण्डलों में मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में स्थापित किये जाने वाले समाजवादी अभिनव विद्यालयों में विद्यालय परिसर में सह शिक्षा के आधार पर छात्रावास के निर्माण के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय/असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक

शिक्षकों को मानदेय की व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा की योजनाओं हेतु 2,622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है ।
- जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है ।
- लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध पीठ केन्द्र की स्थापना और आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिये 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरी एवं कॉमन रूम में वाई–फाई की सुविधा हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- बलिया जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा वर्तमान समय की एक मूलभूत

आवश्यकता है । हमारी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में उच्च स्तर की कुशल प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो ।

- जनपद अम्बेडकर नगर, बाँदा और बिजनौर में स्थापित नये इंजीनियरिंग कॉलेजों में कक्षायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं । जनपद आजमगढ़ में नये इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण मार्च, 2016 तक पूर्ण कराकर कक्षायें शैक्षिक सत्र 2016–2017 से प्रारम्भ करायी जायेंगी ।
- जनपद मैनपुरी, कन्नौज तथा सोनभद्र में निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के पठन–पाठन का कार्य शैक्षिक सत्र 2015–2016 से एच.बी.टी.आई., कानपुर तथा के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर में संचालित कराया जा रहा है ।
- आई.आई.आई.टी., लखनऊ की शैक्षिक सत्र 2015–2016 से कक्षायें आई.आई.आई.टी., इलाहबाद में संचालित की जा रही हैं ।
- जनपद बस्ती एवं गोण्डा में एक–एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- जनपद मिर्जापुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराये जाने हेतु वर्ष 2016–2017 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
- प्रदेश में 12 पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थापित किये जा रहे हैं ।

- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 18 महिला पॉलीटेक्निक संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 15 महिला छात्रावास निर्मित कराये जायेंगे ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

- प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के माध्यम से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार परक कौशलों में प्रशिक्षित किया गया है और अगले साल पॉच लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा ।
- प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 10 संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जायेगा ।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में उच्चीकृत करने हेतु 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुये सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग का कार्य किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त स्कूल/कॉलेजों को आच्छादित करने का लक्ष्य है । इस हेतु 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को देखते हुये ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार

अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । इस योजना हेतु 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 में प्रदेश में 1,800 ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना कराते हुए 36,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- वर्ष 2016–2017 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 ग्रामोद्योगी इकाईयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है जिससे 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा ।
- समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना तथा इनोवेशन पुरस्कार की योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति, 2016 बनाई जा रही है । इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्ट–अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है जिसके अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट–अप तथा वेंचर कैपिटल फण्डिंग स्टार्ट–अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय / चिकित्सा संस्थानों–के.जी.एम.यू., एस.जी.पी.जी.आई., डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान तथा ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के लिये 4,572 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2015–2016 से 1,697 करोड़ रूपये अधिक है ।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये वर्ष 2015–2016 में दी गई धनराशि 221 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 के लिये धनराशि 310 करोड़ रुपये प्रस्तावित है ।
- राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा को शैक्षणिक सत्र 2016–2017 से संचालित किये जाने का लक्ष्य है ।
- जनपद चन्दौली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है तथा जनपद जौनपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
- जनपद कन्नौज में हृदय एवं कैंसर रोगों की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हृदय रोग संस्थान एवं कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम/समुचित उपचार हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ में शैक्षणिक सत्र 2016–2017 से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।
- हृदय रोग के गम्भीर रोग से पीड़ित मरीजों के बेहतर चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये के.जी.एम.यू. में कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार कराया जा रहा है ।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, नजीबाबाद, बिजनौर की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- के.जी.एम.यू. में चिकित्सा शिक्षा, शोध और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के उददेश्य से नये विभाग खोले जायेंगे जिनमें इन्स्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक साईन्सेज, इन्स्टीट्यूट ऑफ वीमेन हेल्थ, इन्स्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थैल्मोलॉजिकल साईन्सेज तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजिकल साईन्सेज मुख्य हैं ।

खेल

हमारा दृढ़ मत है कि आपसी सौहार्द, एकता एवं भाईचारे तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिये जाने के लिये खेलकूद से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रतिभाओं से भरा हुआ है । मुख्य चुनौती उन प्रतिभाओं को सँवारने, विकसित करने एवं बेहतर सुविधायें, प्रशिक्षण एवं मौके उपलब्ध कराने की है । इस हेतु हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ।

- जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वर्ष 2016 में रियो डि जेनेरियो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक खेलों में गोल्ड, सिल्वर तथा काँस्य पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि क्रमशः 6 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये एवं 2 करोड़ रुपये तथा इसी प्रकार टीम वर्ग में क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये एवं 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी । ओलम्पिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी ।
- राज्य के भूतपूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की राशि दो गुनी करते हुये क्रमशः 10,000 रुपये, 6,000 रुपये एवं 4,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाने एवं अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।
- खिलाड़ियों को कुशल प्रशिक्षण देने के लिये अच्छे प्रशिक्षकों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु उनके मानदेय में दुगनी वृद्धि की गई है जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आ सके ।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की नीति बनाई गई है ।

कमजोर वर्गो की सामाजिक सुरक्षा और हिस्सेदारी के लिए

- ''समाजवादी पेंशन योजना'' के लिए वर्ष 2015–2016 के लिये 45 लाख लाभार्थी का लक्ष्य रखा गया था जिसके लिये 2,727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसे वर्ष 2016–2017 में बढ़ाकर 3,327 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जिससे 55 लाख लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सकेगा ।
- वृद्ध एवं अशक्त जनों के लिये गृहों के संचालन हेतु 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण हेतु अधिकरण /अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1,550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व दशम्/ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 1,950 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 1,092 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 683 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिये लिये क्रमशः 121 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 30 लाख रुपये, 154 करोड़ रुपये, 82 करोड़ रुपये तथा 41 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- सीवर सफाई के दौरान मृत होने वाले सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की नई योजना लायी जा रही है जिसके लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर उन्हें निःशुल्क मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा दिये जाने की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- "सबके लिये आवास (शहरी मिशन)" योजना हेतु 277 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

विकलांग कल्याण

- डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवशेष निर्माण कार्यो, विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु क्रमशः 28 करोड़ रुपये, 35 करोड़ रुपये तथा 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- मूकबधिर बालिकाओं को शिक्षित करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद गोरखपुर में राजकीय संकेत इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना के लिये 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये दो जनपदों में आवासीय संकेत इण्टर कॉलेजों की स्थापना हेतु 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- दृष्टिबाधित बालिकाओं को शिक्षित करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद बाँदा एवं मेरठ में राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कॉलेज की स्थापना के लिये 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल कल्याण

महिलायें और बच्चे हमारी जनसंख्या के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी सामाजिक–पारिवारिक व्यवस्था और खुशहाली का आधार

है । महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल और उनका संरक्षण हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व है ।

- गर्भवती महिलाओं हेतु फीडिंग कार्यक्रम के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अति कुपोषित बच्चों की फीडिंग योजना के लिये 125 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है ।
- पति की मृत्य के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये 541 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की निराश्रित महिलाओं के लिये 96 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित वृद्ध महिला आश्रम योजना के लिये रुपये 6 करोड़ 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार अल्पावास, पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 11 जनपदों में यह योजना संचालित की जा रही है । इसके लिये 12 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को इको चाईल्ड फ्रेन्डली बनाये जाने हेतु व अतिरिक्त टॉयलेट व किचन की व्यवस्था

कर उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 2,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण का लक्ष्य है जिसके लिये 13 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बाल पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये 3,220 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

वर्ष 2015–2016 में 100 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया और 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- अल्पसंख्यक समुदाय की पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2016–2017 में 537 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 153 करोड़ रुपये तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
- मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु 394 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान के लिये 395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- दारूल मुन्सफीन (शिब्ली एकेडमी) आजमगढ़ को पुस्तकालय निर्माण के लिये 05 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ।
- कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी बनवाने के लिये धनराशि 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दी गई है ।
- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में उर्दू मास कम्युनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर खोला जाएगा ।

बुनकरों के लिए

- पॉवरलूम विकास योजना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिये पेंशन योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- पॉवरलूम बुनकरों की भाँति हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति कराने हेतु 5 करोड़ रुपये तथा धुनकरों को सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति कराने हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

समाज को स्वस्थ रखने में सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं का विशेष महत्व है । निर्धन, निम्न आय और मध्यम आय वर्गीय परिवारों को सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवायें मुफ्त या अल्प फीस पर सुलभ कराने के लिये हमारी सरकार ने विगत वर्षो में उल्लेखनीय प्रयास किये हैं ।

- प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं पैथोलॉजी जाँचों की सुविधा निःशुल्क कर दी गयी है ।
- प्रदेश के 18 मण्डलीय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रक्रियाधीन है ।
- प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक एवं बर्न यूनिटों की स्थापना हेतु 6 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- दवाओं की खरीद की मद में 519 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2015–2016 की तुलना में 58 करोड़ रुपये अधिक है।
- उपकरणों के क्रय हेतु 306 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- शहरों और गाँवों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के चिकित्सालयों की स्थापना, शैय्या वृद्धि तथा उपकरणों की व्यवस्था हेतु 37 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 लाख परिवारों को चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 4,576 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है ।
- वर्ष 2016–2017 में 30 राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर के लिये 19 करोड़ रुपये की

बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । इस प्रकार प्रदेश में वर्तमान में स्थापित सभी राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र फीडर के माध्मय से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्या वाले संयुक्त/महिला व अन्य चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जामिया हॉस्पिटल, पीलीकोठी, वाराणसी को ऑपरेशन थियेटर के सुदृढ़ीकरण हेतु डेढ़ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

खाद्य तथा रसद

- प्रदेश के 10 जनपदों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर डबल फोर्टीफाइड नमक के वितरण के लिये लगभग 134 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रदेश में प्रथम चरण में जनवरी, 2016 से 28 जनपदों में लागू कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण में शेष 47 जनपदों में मार्च, 2016 से लागू किया जायेगा ।
- मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक कम्प्यूटरीकरण कराया गया है । लगभग 3 करोड़ 87 लाख राशन कार्डों का डाटाबेस तैयार किया गया तथा 3 करोड़ 77 लाख

राशन कार्डों पर डिजिटल सिग्नेचर करके बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है ।

शांति, सुरक्षा और न्याय

महोदय,

हमारा दृढ़ मत है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था एक सभ्य समाज की पहली आवश्यकता और पहचान है । जनसामान्य में सुरक्षा की भावना होना सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है ।

- सेवाकाल के दौरान वीरतापूर्ण कार्य करते हुए शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को अहेतुक सहायता राशि में वृद्धि कर इसे रुपये 20 लाख कर दिया गया है ।
- वीमेन पॉवर लाइन 1090 की सफलता के दृष्टिगत इस सेवा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।
- डायल 100 सेवा के प्रदेश के व्यापक विस्तार के लिए 456 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुलिस थानों तथा पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का पहली बार मानकीकरण कराते हुये उन्नत एवं आकर्षक रूप प्रदान किया गया है जिससे पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी ।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 216 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- समेकित यातायात प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके शहर के यातायात को सुगम बनाया जायेगा । इस प्रणाली को प्रदेश के 12 महानगरों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 111 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम लखनऊ नगर में नवम्बर, 2014 से लागू है और अब इसे 11 और नगरों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है । इसके लिए 161 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) की भाँति स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एस.डी.आर.एफ.) के गठन के लिए 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के थानों में 02–02 सी.सी.टी.वी. कैमरे तथा सोलर फोटोवोल्टइक सेल लगाये जाने की योजना है।
- लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज एवं झाँसी में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

न्याय

- मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ के गोमती नगर में निर्माणाधीन नवीन भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है ।

- अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 500 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन/संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- अधीनस्थ न्यायालयों के सुरक्षा हेतु न्यायालय परिसर की बाउन्ड्रीवॉल के सुदृढ़ीकरण हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है ।
- अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है ।

अधिवक्ता कल्याण

- अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 40 करोड़ रुपये की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के निवर्तन पर रखा जाना प्रस्तावित है ।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्पस फण्ड बनाए जाने के लिये 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

- कारागारों के निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 398 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में 39 कारागारों में आर.ओ. प्लाण्ट की स्थापना करायी जा रही है शेष कारागारों में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में आर.ओ. प्लाण्ट स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है ।
- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 43 कारागारों में सी.सी.टी.वी. सर्विलांस इकाईयों एवं 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर की स्थापना संबंधी कार्य कराया जा रहा है । शेष कारागारों में सी.सी.टी.वी. सर्विलांस व 10 संवेदनशील कारागारों में जैमर लगाये जाने की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कराये जाने का प्रस्ताव है ।
- प्रदेश के अवशेष समस्त कारागारों व जनपद न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है । ई–प्रिजन योजना लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।
- जनपद ललितपुर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वन, वन्य जीवन, पर्यावरण एवं पर्यटन

पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने में वनावरण, वन्य जीवन और वृक्ष आच्छादन के महत्व के मद्देनजर हमारी सरकार ने प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु वन विभाग का नाम परिवर्तित कर वन एवं वन्य जीवन विभाग किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण में वर्ष 2013 की तुलना में 112 वर्ग किलोमीटर (0.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी है । उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले पॉच राज्यों में सम्मिलित है ।
- प्रदेश में वर्ष 2015–2016 में 5 करोड़ 61 लाख पौधों का रोपण किया गया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है । प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं ।
- पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आगरा के राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया तथा प्रत्येक जनपद में बर्ड वॉच कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

- दुधवा टाइगर रिजर्व के विकास के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- हैनोवर, जर्मनी स्थित चिड़ियाघर के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था तथा तितली पार्क के निर्माण के लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । कानपुर प्राणि उद्यान में भी तितली पार्क का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
- जनपद सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वर्ष 2016–2017 में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किये जाने, मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने, नवाबगंज पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार तथा लाख बहोसी पक्षी विहार का विकास किये जाने के लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किये जाने के लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वेटलैण्ड्स के ईकोलॉजीकल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्य जीवों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की स्थाई व्यवस्था के

लिये वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

- वर्ष 2015 में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु ट्रवेल राइटर्स कानक्लेव का आयोजन किया गया । जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हॉट बैलून प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में पहली बार किया गया ।
- इसके अतिरिक्त गंगा महोत्सव, आजमगढ़ उत्सव तथा महाभारत उत्सव आदि का आयोजन भी किया गया ।
- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुनर्निर्माण एवं उच्चीकरण, आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना, सैफई–इटावा में पर्यटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण तथा पर्यटन पुलिस बल का गठन राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है ।

राजकोषीय सेवायें

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 57,940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 19,250 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय

वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है ।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 16,320 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है ।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य करोड़ 5,124 रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

- प्रस्तुत बजट का आकार तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ रुपये (3,46,935 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2016–2017 के बजट के सापेक्ष 14.6 प्रतिशत अधिक है ।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष

2015–2016 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है ।

- बजट में तेरह हजार आठ सौ बयालीस करोड़ रुपये (13,842 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2016–2017 में तीन लाख चालीस हजार एक सौ बीस करोड़ इकसठ लाख रुपये (3,40,120.61 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

- कुल प्राप्तियों में दो लाख इक्यासी हजार पाँच सौ पचपन करोड़ चौवालीस लाख रुपये (2,81,555.44 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा अट्ठावन हजार पाँच सौ पैंसठ करोड़ सत्रह लाख रुपये (58,565.17 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश दो लाख छः हजार आठ सौ तिरानवे करोड़ साठ लाख रुपये (2,06,893.60 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश एक लाख पाँच हजार छः सौ सैंतीस करोड़ दस लाख रुपये (1,05,637.10 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये (3,46,934.78 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में दो लाख तिरपन हजार तीन सौ चौवन करोड़ चौवन लाख रुपये (2,53,354.54 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरानवे हजार पाँच सौ अस्सी करोड़ चौबीस लाख रुपये (93,580.24 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- आयोजनागत पक्ष के व्यय के लिये एक लाख छब्बीस हजार छः सौ तिरासी करोड़ छियासठ लाख रुपये (1,26,683.66 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2016–2017 में अट्ठाईस हजार दो सौ करोड़ नब्बे लाख रुपये (28,200.90 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में उनचास हजार नौ सौ साठ करोड़ अट्ठासी लाख रुपये (49,960.88 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है । इसमें विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना–"उदय" के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले तेरह हजार तीन सौ तीन करोड़ रुपये

(13,303 करोड़ रुपये) के बन्ध पत्र सम्मिलित हैं जिनकी राशि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (यथासंशोधित) में निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा के बाहर रखी जायेगी। इस राशि को छोड़ने पर राजकोषीय घाटा छत्तीस हजार छः सौ सत्तावन करोड़ अट्ठासी लाख रुपये (36,657.88 करोड़ रूपये) होता है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है ।

- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.3 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जायेगा ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् छः हजार आठ सौ चौदह करोड़ सत्रह लाख रुपये (6,814.17 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

लोक लेखे से सात हजार दो सौ करोड़ रुपये (7,200 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2016–2017 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम तीन सौ पचासी करोड़ तिरासी लाख रुपये (385.83 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2016–2017 में प्रारम्भिक शेष एक सौ उनासी करोड़ पचपन लाख रुपये (179.55 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष पाँच सौ पैंसठ करोड़ अड़तीस लाख रुपये (565.38 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति का आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में मिलकर काम करें और सरकार की तरफ से

आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इस दिशा में कदम–से–कदम मिलाकर काम करेगी।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2016–2017 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ 23, शक संवत् 1937,
तद्नुसार,
दिनाँक : 12 फरवरी, 2016